लीबिया में मिला गैस और तेल का भंडार

गदामेस बेसिन में बड़ी खोज, भारत को मिलेगा रणनीतिक फायदा

नई दिल्ली, 28 अप्रैल: भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है, जहां लीबिया के गदामेस बेसिन में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला है. इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. लीबिया के गदामेस बेसिन में भारतीय कंपनियों द्वारा तेल और गैस का नया भंडार खोजा गया है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस खोज की आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए इसे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी सफलता बताया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई और परियोजना में शामिल कंसोर्टियम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह खोज न केवल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को भी मजबूती प्रदान करेगी.

यह महत्वपूर्ण खोज लीबिया के गदामेस बेसिन स्थित कॉन्ट्रैक्ट एरिया 95/96 में की गई है.

> भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है. ऐसे में विदेशों में ऊर्जा संपत्तियों में निवेश और नई खोजें देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यह खोज उसी दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है. मंत्रालय ने कहा कि यह सफलता भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है. साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित करती है. भारत लगातार विभिन्न देशों में ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया ने टेक कंपनियों पर सख्ती

नई दिल्ली, 28 अप्रैल. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है. इसके तहत मेटा, गूगल और टिकटॉक को समाचार सामग्री के उपयोग के बदले स्थानीय मीडिया संस्थानों को भुगतान करना होगा.

सरकार के 'न्यूज़ बार्गेनिंग इंसेंटिव' प्रस्ताव के अनुसार, यदि ये कंपनियां स्थानीय समाचार प्रकाशकों के साथ व्यावसायिक समझौता नहीं करती हैं, तो उनकी देश में होने वाली कमाई पर 2.25 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. इस कर से जुटाई गई राशि का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में पत्रकारिता को आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम बताया है. उनका कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां समाचारों

कच्चे तेल की कीमत 109 डॉलर के पार

महंगे तेल और होर्मुज तनाव से निवेशकों की चिंताएं बढ़ीं

ब्रेंट क्रूड 1.08 डॉलर बढ़कर 102.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

नई दिल्ली, 28 अप्रैल. पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक वार्ताओं में बाधा आने के बाद एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को व्यापक गिरावट देखने को मिली. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव ने निवेशकों के जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित किया.

होर्मुज जलडमरूमध्य, जो एशिया के लिए एक प्रमुख तेल मार्ग है, के बंद होने की आशंका ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर धकेल दिया. जून डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड का भाव 1.11 डॉलर बढ़कर 109.34 डॉलर प्रति बैरल हो गया. इसी तरह जुलाई अनुबंध वाला ब्रेंट क्रूड 1.08 डॉलर बढ़कर 102.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा. अमेरिकी क्रूड 96 सेंट की बढ़त के साथ 97.33 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल पर था और संघर्ष के दौरान यह 120 डॉलर तक पहुंच चुका था.

तेल की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव विशेष रूप से उन देशों के लिए चिंता का विषय है जो ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं, जैसे कि जापान और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएं.

> पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर एशियाई शेयर बाजारों पर देखने को मिला, जहां निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाते हुए बिकवाली का रुख अपनाया. जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंग सेंग और शंघाई कंपोजिट जैसे प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि महंगे ऊर्जा आयात की चिंता ने बाजार की धारणा को कमजोर किया. हालांकि, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सीमित बढ़त के साथ अलग रुख दिखाता नजर आया, लेकिन कुल मिलाकर क्षेत्रीय बाजार दबाव में रहे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं.

नायडू-वैष्णव ने गूगल एआई हब शुरू किया

विशाखापत्तनम, 28 अप्रैल. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की नींव रखी.

इस एआई हब में गूगल करीब 15 अरब डॉलर निवेश करेगा, जो कि देश के इतिहास में आया अब तक का सबसे बड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है.

भूमि पूजन समारोह में बोलते हुए चंद्रबाबू नायडू ने गूगल और परियोजना में उसके साझेदारों, अदाणीकनेक्स और एयरटेल नेक्स्ट्रा से सितंबर 2028 तक परियोजना को पूरा करके उद्घाटन करने का आग्रह किया. साथ ही, उन्होंने परियोजना के शीघ्र पूरा होने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने आगे कहा कि गूगल का यह निवेश विशाखापत्तनम के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक गेम चेंजर है.

उन्होंने याद करते हुए कहा कि 30 साल पहले, जब उन्होंने साइबराबाद को एक आईटी सिटी के रूप में स्थापित करने की नींव रखी थी, अब वह वेल्थ क्रिएशन का केंद्र बन गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा और आंध्र प्रदेश देश के लिए एआई डेटा गेटवे के रूप में उभरेगा.उन्होंने कहा, 'गूगल, जिसने एक सर्च इंजन के रूप में शुरुआत की थी, अब भारत के विकास का इंजन बन रहा है.

> संबोधन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि एक देश के रूप में भारत कई तकनीकी विकास चक्रों से चूक गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत नई तकनीकी विकास प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में की गई पहलों के बदौलत भारत आईटी सेवाओं का अग्रणी बन गया, लेकिन सेमीकंडक्टर, सर्वर, लैपटॉप और मोबाइल फोन के निर्माण में पिछड़ गया. हालांकि, मेक इन इंडिया पहल के शुभारंभ के साथ पिछले एक दशक में स्थिति पूरी तरह बदल गई है.

सोना चांदी में आई गिरावट

2,600 रुपए सस्ता हुआ सोना

148 हजार रुपए आई चांदी

नई दिल्ली में 28 अप्रैल सोना 1,49,557 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,38,339 प्रति किलो पर आ गई है. दोनों की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 26 हजार सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी भी अपने उच्चतम स्तर से तेज गिरावट के बाद काफी नीचे आ गई है.

को सोने और चांदी के बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,629 रुपए गिरकर ?1,49,557 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. इससे पहले यह करीब 1,51,000 के स्तर पर थी. वहीं चांदी की कीमत में भी तेज गिरावट दर्ज की गई और यह ?5,381 टूटकर 2,38,339 प्रति किलो रह गई, जबकि पिछले सत्र में यह 2,49,000 के करीब थी.

हाल के हफ्तों में सोने में आई तेजी अब मुनाफावसूली के दबाव और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के चलते कमजोर पड़ रही है. ईरान-क्षेत्र में तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से निकासी शुरू कर दी है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा है.

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 'ऐतिहासिक' : जयशंकर

नई दिल्ली, 28 अप्रैल. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आर्थिक सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत करता है. यह समझौता न केवल व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और सेवा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व अवसर भी पैदा करेगा.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक करार दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयशंकर ने इस समझौते से मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, यह समझौता केवल व्यापारिक लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग, रणनीतिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के नए आयाम खोलता है. इस एफटीए के माध्यम से भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है. व्यापार बाधाओं में कमी, टैरिफ में राहत और बाजार तक बेहतर पहुंच से दोनों देशों के निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा. भारतीय उत्पाद—विशेषकर कृषि, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं—को न्यूजीलैंड के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मिलेंगे, वहीं न्यूजीलैंड के डेयरी, कृषि और शिक्षा क्षेत्र को भारत में नए अवसर प्राप्त होंगे.

इस एफटीए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लागू होते ही भारत के 100 फीसदी वस्तु निर्यात पर शून्य शुल्क लागू होगा. इसका मतलब है कि भारतीय उत्पाद अब न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी टैरिफ बाधा के प्रवेश कर सकेंगे. साथ ही, सभी टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्ति से व्यापारिक प्रक्रियाएं और अधिक सरल और पारदर्शी बनेंगी. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार नीति के तहत फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म भी लागू किया जाएगा, जिससे इनपुट्स की उपलब्धता और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी.

> यह समझौता खास तौर पर किसानों, एमएसएमई, कारीगरों, महिलाओं और युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. कृषि उत्पादों—जैसे फल, सब्जियां, कॉफी, मसाले और अनाज—को नए बाजार मिलेंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है. वहीं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.

मदर डेयरी ने नये उत्पाद पेश करने की घोषणा की

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल मदर डेयरी ने इस बार गर्मी के सीजन में 30 से अधिक नये उत्पाद बाजार में उतारने की मंगलवार को घोषणा की और कहा कि इससे उससे प्रमुख श्रेणियों में कारोबार 30 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है.

कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इन मूल्य-वर्द्धित उत्पादों को पूरे सीजन के दौरान चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जायेगा. इंडल्जेंस, सेहत, सुविधा और क्षेत्रीय पसंद जैसे प्रमुख पहलुओं पर आधारित ये उत्पाद हर उम्र के उपभोक्ताओं और बदलती जीवनशैली के लिए विविध और आकर्षक विकल्प पेश करते हैं.

आइसक्रीम सेगमेंट में ब्रांड लगभग 20 नये उत्पाद ला रहा है. इनमें पहली बार टू-इन-वन मटका और टब फॉर्मेट, प्रीमियम क्राफ्टेड रेंज, तथा युवाओं को पसंद आने वाले फ्लेवर्स जैसे क्रीम चीज पिस्ता कोन और पिस्ता कुल्फी कसाटा शामिल हैं. इसके अलावा, गो-लो सब-ब्रांड के तहत कम कैलोरी वाली आइसक्रीम की नयी रेंज भी पेश की जा रही है, जो तीन स्वादिष्ट फ्लेवर्स- चोको आल्मंड, शाही मेवा और केसर पिस्ता टिल्ला कुल्फी- में उपलब्ध होगी.

> कंपनी अपने यूएचटी दूध पोर्टफोलियो का भी विस्तार करेगी, जिसमें काउ मिल्क और स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क को जम्मू एवं कश्मीर जैसे बाजारों में पेश किया जायेगा, ताकि सुविधाजनक और लंबी शेल्फ-लाइफ वाले विकल्पों की बढ़ती मांग पूरी की जा सके.

भारत-अमेरिकी वाणिज्य मंडल ने की राजस्थान चैप्टर की शुरुआत

नयी दिल्ली. भारत-अमेरिकी वाणिज्य मंडल ने अपने राजस्थान चैप्टर की शुरुआत की है, जो राज्य स्तर पर भारत-अमेरिका व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक विस्तार है.आईएससीसी की मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में उम्मीद जतायी गयी है कि यह चैप्टर सीमा पार साझेदारी को सुविधाजनक बनाने, नीतिगत संवाद को बढ़ाने और भारतीय तथा अमेरिकी व्यवसायों के बीच क्षेत्र-विशिष्ट के लिए सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा.

तेजी से बढ़ रही समृद्ध लोगों की संख्या

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने वाली कंपनी वीजा की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में समृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसका विस्तार अब मझौले तथा छोटे शहरों में भी तेजी से देखा जा रहा है.

'भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था 2025-26' के नाम से मंगलवार को जारी इस श्वेतपत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि 'समृद्ध भारत' तेजी से बढ़ रहा है और एक नये चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां उपभोग अधिक सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण हो गया है, तथा व्यक्तिगत पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है. अधिक खरीदारी करने की बजाय समृद्ध उपभोक्ता अब ऐसे उत्पाद चुन रहे हैं जो अर्थपूर्ण, दिखने योग्य और बार-बार खरीदने लायक हों.श्वेतपत्र में समृद्ध आबादी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक है. हाल में 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों की संख्या 69 लाख से बढ़कर 130 लाख हो गयी है.

समाचार विशेष

जदयू में 3 नंबर पर पूर्व सांसद चंद्रवंशी

नीतीश कुमार ने बढ़ाया ओबीसी नेता का कद

पटना. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने संगठन में अहम फेरबदल करते हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को बड़ा दायित्व सौंपा है. पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जिससे उनका सियासी कद एक बार फिर बढ़ गया है. पार्टी में अब उनका स्थान शीर्ष नेतृत्व में गिना जा रहा है.

पूर्व सीएम सह राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के बाद संगठन में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है.

दिलचस्प बात यह है कि चंद्रवंशी को हाल के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव से हार मिली तो 2025 विधानसभा चुनाव में राजद के ही राहुल कुमार ने महज 793 वोटों से शिकस्त दी.

आंकड़े बताते हैं कि राहुल कुमार को 86,402 जबकि चंद्रवंशी को 85,609 वोट मिले. यानी हार का अंतर बेहद कम रहा, जिसने उनके जनाधार को भी साबित किया. लगातार दो करीबी हार के बावजूद छुष्ठ का यह फैसला कई संकेत देता है कि ग्राउंड कनेक्ट वाले नेता पर भरोसा कायम है. अतिपिछड़ा समाज में पकड़ मजबूत करने की कोशिश, चुनावी हार से ज्यादा संगठनात्मक क्षमता को प्राथमिकता के दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा रहा है.

कौन हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी?

पटना जिला के नदवां के मूल निवासी चंदेश्वर प्रसाद के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे. राजनीति से पहले चंद्रवंशी कोयला कारोबार से जुड़े रहे. समता पार्टी से राजनीतिक शुरुआत की. 2013 में जडीयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए. ओबरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े. वे विधान पार्षद के अलावा बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. 2019 में जहानाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए. चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना सिर्फ पद देना नहीं, बल्कि आगे की राजनीति के लिए रणनीतिक संकेत है. जेडीयू अब ऐसे नेताओं को आगे ला रहा है जो जमीन पर सक्रिय हों और सामाजिक समीकरण साध सकें.

यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा?

लखनऊ. यह ऐसा प्रश्न बन गया है, जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है. 2022 में सरकार बनने के बाद से पिछले चार साल में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

एकाध वैकेंसी होने पर मंत्री बनाना या एकाध विभाग बदलना अलग बात है. लेकिन चार साल से ज्यादा समय तक मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं होना भी एक अनहोनी सी बात है. ऊपर से इसे लेकर ज्यादा चर्चा इस वजह से भी है कि हर दो या तीन महीने पर मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा होती है और फिर चर्चा रूक जाती है.

पिछले दिनों ऐसा लगा था कि अब निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. दिल्ली और लखनऊ के बीच भागदौड़ शुरू हो गई थी. जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव है. इसलिए अगर नए सिरे से जातीय समीकरण साधने का प्रयास होता है तब भी मंत्रियों को काम करने के लिए समय मिलना चाहिए.

सारी भागदौड़ के बावजूद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी. अब भी प्रयास चल रहे हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की. हफ्ते दिन तक फिर कयास चलती रहेगी.

बिहार में कांग्रेस की मुश्किल

पटना. बिहार में कांग्रेस पार्टी के छह विधायक जीते थे. चुनाव नतीजों के कुछ दिन बाद राहुल गांधी ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला कर एक बैठक की थी और कहा गया था कि जल्दी ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा. लेकिन पांच महीने बाद भी कांग्रेस ने विधायक दल का नेता नहीं चुना है.

जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेता चुनेगी भी नहीं क्योंकि कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को पता है कि उसका विधायक दल ही नहीं रहने वाला है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सभी छह विधायक पाला बदल सकते हैं. इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार की राजनीति से पल्ला झाड़ लिया है.

सोचें, राहुल गांधी ने अपने करीबी कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया था और दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. उनके नेतृत्व में कांग्रेस 19 से घट कर छह सीट पर आ गई और अब वे छह विधायक भी पार्टी के साथ नहीं हैं. तीन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के समय पाला बदल लिया था. कोईरी समाज के सुरेंद्र कुशवाहा, दलित समाज के मनोज विस्वास और आदिवासी समाज के मनोहर प्रसाद सिंह राज्यसभा में वोटिंग से गैरहाजिर रहे थे. उसके बाद से ही उनको भाजपा में शामिल होने की चर्चा है.

इनके अलावा तीन अन्य विधायकों में दो मुस्लिम हैं. कहा जा रहा है कि दोनों मुस्लिम विधायक जदयू में और चार हिंदू विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे. राजद के भी मुस्लिम विधायक फैसल रहमान के जदयू में जाने की चर्चा है. राज्यसभा चुनाव में वे भी गैरहाजिर रहे थे.

विशेष राजनीति की बारीकियां खुद सीखा रहे नीतीश कुमार

जनता की डिमांड बनने की तैयारी में निशांत

पटना. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार या फिर उनके पुत्र निशांत कुमार ने भले राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में जाने से इनकार कर दिया हो पर सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने से, अपने चाहने वाले, अपने समर्थक या फिर पार्टी की मजबूत भविष्य को संवारने से इनकार नहीं किया है.

देर आए पर दुरुस्त आए की तर्ज पर निशांत कुमार की ग्रूमिंग चालू है और यह कोई और नहीं बल्कि उनके पिता नीतीश कुमार की देख रख में चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति का पाठ किताबों से नहीं बल्कि समाज के सरकारों के रास्ते पढ़ा रहे हैं. सीएम पद छोड़ने के बाद स्थिति यह है कि पिता पुत्र के बीच बॉन्डिंग काफी बढ़ गई है और नीतीश कुमार भी निशांत के लिए काफी समय निकाल रहे हैं. वैसे भी नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य यू ही नहीं करार दिए गए हैं. दरअसल, नीतीश कुमार फिलहाल राजनीति में प्री-कॉशन रख कर निशांत कुमार को एक जिम्मेदार नेतृत्व की ओर ले जा रहे हैं. चाहते यह हैं कि निशांत कुमार अपनी आंखों से राजनीति को परखे और रुचि जाग जाए तो राजनीति की डोर को मजबूती से पकड़े.

क्या चाहते हैं नीतीश कुमार!- नीतीश कुमार राजनीति को जबरन निशांत कुमार के सिर पर थोपना नहीं चाहते हैं. साथ ही साथ वे अन्य नेता पुत्रों की तरह निशांत कुमार की एंट्री भी नहीं चाहते हैं. वे चाहते है बिहार की जनता की डिमांड निशांत कुमार बने. ऐसा इसलिए भी कि उन पर परिवारवाद का वह स्वरूप न दिखे जो अन्य नेता पुत्रों के राजनीति में आने पर दिखा है.

> **बढ़ा रहे हैं इंटरेक्शन**
>
> राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत के लिए काफी मजबूत आधार बनाने में जुट गए हैं. और इसके लिए निशांत कुमार के इंटरेक्शन के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करा रहे हैं. कुछ दिन पहले प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर बिहार की राजनीति की नब्ज पकड़ने की कोशिश की. इधर निशांत कुमार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर लगातार मंथन पर मंथन कर रहे हैं और लगातार जिलों के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे है.